

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
06.08.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1921

परमाणु संयंत्रों और ईंधन के लिए समझौता

1921. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार और अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने तथा ईंधन की आपूर्ति करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से देश हैं, जिनके साथ समझौते किए जा रहे हैं;
- (ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और
- (घ) वे कौन-कौन से स्थान हैं, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बावजूद स्थापित नहीं किए जा सके और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

- (क) जी, हाँ।
- (ख) रूस के तकनीकी सहयोग से बन रही कुडनकुलम विस्तार परियोजना नामतः कुडनकुलम तथा नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 (केकेएनपीपी यूनिट 3 तथा 4) को सरकार द्वारा (ग) प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दिए गए हैं। इस परियोजना को चालू वर्ष में प्रारंभ करने के लिए तैयार किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) एवं फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमरीका की कंपनियों के बीच चल रही बातचीत, बड़ी क्षमता वाले नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करने के लिए, परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने की दिशा में केन्द्रित है। इस मामले में, सरकार का अंतिम निर्णय इन बातचीतों के निष्कर्ष पर निर्भर है। भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के लिए फ्रांस, रूस, कजाखिस्तान, उजबेकिस्तान एवं कनाडा के साथ बातचीत की गई है, एवं इन देशों के साथ करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (घ) उपर्युक्त (ख) एवं (ग) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।
